डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 62 ● अंक 3 ● भोपाल ● 1-15 जुलाई, 2018 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/– ● आजीवन शुल्क 1500/–

प्रशिक्षण के बाद व्यवहार में आना चाहिये कौशल उन्नयन

सहकारिता राज्य मंत्री श्री सारंग ने सहकारी सम्मेलन एवं आर.पी.एल. (रिटेल) प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण प्राप्त सहकारी संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि प्रशिक्षण लेना भर पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में कौशल उन्नयन आना चाहिये। श्री सारंग समन्वय भवन में म.प्र. राज्य सहकारी संघ के आयोजन राज्य–स्तरीय सहकारी कौशल विकास सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। प्रशासक अपेक्स बैंक श्री रमाकांत भार्गव और आयुक्त सहकारिता श्री केदार शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता विभाग ने सहकारी मंथन से निकले सुझावों पर अमल कर नवाचारी प्रयोग किये हैं। झाबुआ जिले में नवाचार के तहत कड़कनाथ मुर्गा–पालन सहकारी समितियों से लोगों को जोड़ा गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम आये हैं। हाल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने झाबुआ जिले के कड़कनाथ मुर्गा–पालन से जुड़े किसानों से चर्चा की और सराहना की। सहकारिता के माध्यम से झाबुआ में हजारों किसानों ने नवाचार किया है। इसी तरह के नवाचार पर्यटन समितियों द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन–औषधि कार्यक्रम के तहत सहकारिता विभाग द्वारा राज्य सहकारी जन–औषधि विपणन संघ का पंजीयन किया गया है।

श्री सारंग ने कहा कि एक हजार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं को बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था में परिवर्तित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सहकारी क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के कर्मचारियों–अधिकारियों का कौशल उन्नयन किया जा रहा है। सभी व्यक्तियों में कोई न कोई कौशल एवं हुनर होता है, जरूरत है उनमें मौजूद संभावनाओं को तराशने की।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

(पृष्ठ 1 का शेष)

प्रशिक्षण के बाद व्यवहार में आना चाहिये कौशल उन्नयन

सहकारिता विभाग व्यक्तियों को ऐसे अवसर और मदद देता है, जिससे उनके हुनर और कौशल को तराशा जा सके। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग में जो सीखा है, उसे जमीन पर उतारना है। दायित्व को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना है। सहकारी संघ द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में अभी तक 2000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत म.प्र. राज्य सहकारी संघ द्वारा पैक्स के प्रशिक्षित विक्रेताओं को प्रमाण पत्र वितरित किये तथा प्रशिक्षणार्थियों से अपेक्षा कि वें अपने कार्य व व्यवहार में बदलाव लाये ताकि सहकारिता की गुणवत्ता कायम हो सकें। इस क्षेत्र मे प्रदेश तथा आप लोग पहले प्रतिभागी है। उन्होंने राज्य सहकारी संघ को बधाई दी तथा कहा कि अभी 2000 प्रशिक्षित किये है 3000 की ओर स्वीकृति प्राप्त हो गई है इसे एक लाख तक ले जाने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू है तथा किसी भी व्यवस्था के संचालन मे इनका संतुलन होना जरूरी है। श्री रमाकांत भार्गव ने कहा कि सहकारिता केवल किसानों तक ही सीमित नहीं है, इससे अन्य वर्ग भी जुड़े हैं। कौशल उन्नयन से विभाग की अच्छी छबि बनेगी। सहकारिता आयुक्त श्री केदार शर्मा ने सम्मेलन के संबंध में जानकारी दी कहा कि , कौशल प्रशिक्षण अलग तरह का कार्य है। कौशल विकास से क्षमता में वृद्धि होती है जिससे चुनौतियों का मुकाबला तथा दायित्व निर्वहन में मदद मिलेगी। इस अवसर पर प्रदेश की प्रथम जन औषधि वितरण सहकारी संस्था को प्रमाण पत्र भी सौंपा गया। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने किया। इस मौके पर एम.पी. कॉन के एम.डी. श्री बी.बी. साहू, भोपाल को–ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि. भोपाल के अध्यक्ष श्री जीवन मैथिल, संतोष मीना तथा सहकारिता विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित (माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)

सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध
प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
ई–8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड–462 039
फोन.–0755 2725518, 2726160 फेक्स–0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
किला मैंदान, इंदौर
फोन : 0731-241908, 9926451862

कुशल व सफल सहकारिता के लिए सार्थक प्रशिक्षण आवश्यक : शरद जैन

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत जबलपुर के प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित

जबलपुर। जब तक सहकारी संस्थाओं के विक्रेता अपने कार्य क्षेत्र में कुशलता प्राप्त नहीं करते तब तक सहकारिता की सफलता भी मुश्किल है क्योंकि सहकारिता क्षेत्र का विकास इन्हीं सहकारी कर्मियों पर निर्भर है और इसके लिए प्रशिक्षण ही सार्थक समाधान है। ये विचार प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री शरद जैन ने एन.एस.डी.सी. नई दिल्ली और मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के परस्पर सहयोग से सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में आयोजित आर.पी.एल. (रिटेल) प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किये। राज्य मंत्री ने प्रमाण पत्र वितरित करते हुए प्रशिक्षार्थियों के प्रति अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त की और सहकारी क्षेत्र में विक्रय के दौरान प्रशिक्षण का उपयोग करने की अपेक्षा की।

विशेष अतिथि के रूप में पी. एस. तिवारी संयुक्त आयुक्त सहकारिता ने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र भी अछूता नहीं है और निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से नित नए प्रयोग हो रहे हैं। विशेष अतिथि के रूप में जी. पी. प्रजापति उपायुक्त सहकारिता ने भी उम्मीद जताई कि ऐसे प्रशिक्षणों से प्रधानमंत्री के सपने साकार होंगे। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के महाप्रबंधक आलोक यादव ने कहा कि राज्य सहकारी संघ ऐसी प्रशिक्षण गतिविधियों के माध्यम से कीर्तिमान स्थापित कर रहा है जो कि प्रेरणादायी है। सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप दुबे ने कहा कि शासकीय व सहकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का आज प्रचार आवश्यक है जिसमें सशक्त माध्यम कुशल प्रशिक्षण ही हो सकता है। कार्यक्रम में योगेन्द्र दुबे ने भी विचार व्यक्त किये।

कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत भाषण केन्द्र के प्राचार्य यशोवर्धन पाठक ने देते हुए राज्य सहकारी संघ व सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। केन्द्र के व्याख्याता एस.के. चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और रिटेल प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किये गए। जबलपुर सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा कला वीथिका सभा भवन में आयोजित इस प्रशिक्षण में प्रदेश के जबलपुर, सतना, रीवा, सिंगरौली, सीधी, मंडला और बालाघाट जिले की सहकारी संस्थाओं के विक्रेताओं ने भाग लिया।

कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता व कार्यक्रम समन्वयक वी.के. बर्वे द्वारा किया गया। अंत में आभार प्रदर्शन भोपाल से पधारे संतोष येड़े ने किया। कार्यक्रम के आयोजन में प्रशिक्षक रितेश कुमार, लेखापाल एन.पी. दुबे, कार्यालय सहायक चेतन गुप्ता और कैलाशचंद्र कहार का सहयोग उल्लेखनीय रहा।

मध्यप्रदेश ने आदर्श उपार्जन का बनाया रिकार्ड

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उपार्जन से जुड़े अधिकारियों की टीम को दी बधाई

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में फसलों का उपार्जन अभूतपूर्व सफलता के साथ पूरा करने के लिए मंत्रालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों को बधाई दी। श्री चौहान ने कहा कि गेहूँ, धान, चना, मूंग, सरसों की खरीदी करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसी बीच कई बड़े निर्णय लेना पड़े और कई कठिनाइयां भी आई। विषम परिस्थितियों के बावजूद सफल और शांतिपूर्ण उपार्जन मध्यप्रदेश के लिये बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए उपार्जन से जुड़ी पूरी टीम की जितनी तारीफ की जाए कम है। सभी संबंधित विभागों ने रात–दिन मेहनत कर उपार्जन के काम को आदर्श स्थिति में लाने का सराहनीय काम किया है। यह सभी विभागों, एजेंसियों, किसानों के समन्वित प्रयासों से संभव हुआ।

श्री चौहान ने प्रदेश में स्थापित आदर्श उपार्जन की व्यवस्था का व्यवस्थित अध्ययन करने और एक मार्गदर्शी दस्तावेज़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य भी मध्य प्रदेश की आदर्श उपार्जन व्यवस्था से प्रभावित है और जानना चाहते है कि सफल उपार्जन की रणनीति जैसे बनती है। श्री चौहान ने कहा कि उपार्जन से जुड़ी संस्थाओं और किसानों का सहयोग और आपसी समन्वय हर स्तर पर सराहनीय रहा है। श्री चौहान ने मंडी, एन.आई.सी., एफ.सी.आई, नाफेड, सहकारी एवं सरकारी बैंको, आर.बी.आई., रेलवे, वित्त विभाग, सहकारिता, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य विभाग, मार्कफेड के अधिकारियों और मैदानी अमले को बधाई दी। उन्होंने प्रशंसा प्रमाणपत्र देने के लिए भी कहा।

जिलों की मार्केटिंग योजना बनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में कृषि उपज की मार्केटिंग के लिये कार्य योजना बनाने पर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उपार्जन की व्यवस्था को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग के संबंध में विशेषज्ञों की कार्यशाला भी बुलाई जाना चाहिये। इसके अलावा किसानों की आय को दोगुनी करने के लिये बेहतर उपायों पर निरंतर विचार विमर्श चलते रहना चाहिये। श्री चौहान ने बिहार और केरल में उपार्जन व्यवस्था का भी अध्ययन करने के निर्देश दिये।

किसानों को मिले 19 हजार 500 करोड़

उल्लेखनीय है कि रबी वर्ष 2018–19 में 96 लाख किसानों से 73.13 लाख मीट्रिक टन गेहूँ और 7.33 लाख किसानों से 19.2 लाख मीट्रिक टन चना, मसूर और सरसों का रिकॉर्ड उपार्जन किया गया है। किसानों को 19 हजार 500 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव खाद्य श्रीमती नीलम शमी राव, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव श्री विवेक अग्रवाल, मंडी आयुक्त श्री फैज अहमद किदवई, भारतीय खाद्य निगम के श्री अभिषेक यादव, नाफेड के श्री अभिषेक सिंह, एनआईसी के अब्राहिम वर्गिस एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

उचित मूल्य की दुकानें होंगी बहुउद्देश्यीय : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री के समक्ष हुआ योजना का प्रस्तुतिकरण

भोपाल। प्रदेश में उचित मूल्य दुकानों को बहुउद्देशीय दुकानों में परिवर्तित करने की योजना बनाई गयी है। प्रयोग के तौर पर प्रथम चरण में एक हजार उचित मूल्य दुकानों को बहुउद्देशीय दुकानों में परिवर्तित किया जायेगा। इन दुकानों में उपभोक्ताओं को एमआरपी से न्यूनतम पाँच प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस व्यवस्था के संचालन के लिये सहकारिता विभाग द्वारा साफ्टवेयर तैयार किया जायेगा। योजना का मंत्रालय में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि योजना को पायलट योजना के स्वरूप में क्रियान्वयन किया जाये। क्रियान्वयन स्वरूप परिणामों की जानकारी प्रस्तुत की जाये। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे।

इस मौके पर बताया गया कि उचित मूल्य दुकानों से उपभोक्ताओं को कम दर पर गुणवत्तायुक्त वस्तुएं उपलब्ध होंगी। इससे उचित मूल्य दुकानों के खुले रहने की अवधि बढ़ेगी। उचित मूल्य दुकानों की उपयोगिता बढ़ेगी। प्रदेश में कुल 22 हजार 396 उचित मूल्य दुकानें हैं, जिनमें 18 हजार 96 दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ नोडल एजेंसी रहेगा। नीतिगत निर्णयों के लिये आयुक्त सहकारिता की अध्यक्षता में एक सक्षम समिति गठित होगी।

मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना

किसानों का ब्याज माफ करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई

इंदौर। राज्य शासन द्वारा डिफाल्टर किसानों के हित में एक नई महत्वपूर्ण योजना लागू की गयी है। इस योजनांतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून 2018 से बढ़ाकर 31 जुलाई,2018 कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 31 जुलाई 2018 तक अपनी बकाया राशि का 50 प्रतिशत मूलधन जमा करने वाले किसान योजना की पात्रता सूची में शामिल हो जाएंगे। योजना के तहत बाद में शेष 50 प्रतिशत मूलधन राशि जमा करने वाले किसानों का पूरा ब्याज भी माफ किया जायेगा।

बताया गया है कि राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्णय अनुसार योजना को गत 12 फरवरी 2018 से लागू मानने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के जिन डिफाल्टर कृषकों द्वारा 12 फरवरी 2018 से 6 अप्रैल 2018 की अवधि में समाधान योजना लागू किये जाने की प्रत्याशा में बकाया मूलधन जमा की गई है, उन्हें भी इस योजना का नियमानुसार लाभ दिया जायेगा।

इस योजना के अंतर्गत इंदौर जिले में कुल 22 हजार 479 डिफाल्टर किसान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना अंतर्गत पात्रता रखने वाले किसान अपने खाते में बकाया मूलधन की न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि 31 जुलाई, 2018 तक जमा कर योजना में भाग ले सकते हैं। इसके पश्चात शेष 50 प्रतिशत बकाया मूलधन राशि जमा करने वाले कृषकों को ऋण लेने की पात्रता सूची में शामिल किया जायेगा। जिले में इस योजना का लाभ अल्पावधि फसल ऋण तथा मध्यावधि परिवर्तित ऋण लेने वाले कृषकों को मिलेगा।

बताया गया है कि 30 जून 2017 पर अल्पावधि फसल ऋण की कालातीत बकाया राशि तथा प्राकृतिक आपदा के कारण पूर्व वर्षो में मध्यावधि ऋण में परिवर्तित किये गये अल्पावधि फसल ऋण की कालातीत बकाया राशि वाले प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) के कृषक सदस्य योजनांतर्गत पात्र होंगे। इस योजना में ऐसे प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सम्मिलित होंगे , जो राज्य शासन की इस समाधान योजना को अंगीकृत करने हेतु सहमत होंगी।

योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता – जिस दिनांक को योजना अंतर्गत बकाया कालातीत ऋणों के निपटारे हेतु समाधान किया जाना है, उस दिनांक को बकाया मूलधन का 50 प्रतिशत न्यूनतम जमा कराया जाना अनिवार्य है।

योजना में भाग लेने हेतु कृषक द्वारा बकाया मूलधन का 50 प्रतिशत राशि अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2018 तक जमा किया जाना होगा। ऋणगृहिता कृषक अपनी सुविधा अनुसार यदि चाहें तो उक्त 50 प्रतिशत मूलधन की राशि किश्तों में भी 31 जुलाई, 2018 तक जमा कर सकते हैं।

समाधान फार्मूला – कृषक से समाधान योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया जायेगा एवं संबंधित कृषक द्वारा बकाया मूलधन की राशि का 50 प्रतिशत चुका देने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी – कृषक का एनसीएल नवीन ऋणमान से तत्काल स्वीकृत किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। कृषक द्वारा जिस दिनांक को शेष आधे मूलधन की राशि चुकायी जायेगी, उसी दिन कृषक को इस राशि के बराबर का शून्य प्रतिशत ब्याज का नवीन नगद ऋण स्वीकृत कर वितरण कर दिया जावेगा और उस दिनांक को खाते में शेष बकाया ब्याज की संपूर्ण राशि माफ कर दी जायेगी। कृषक को नवीन ऋणमान के अंतर्गत उपलब्ध शेष साख सीमा का अतिरिक्त ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वस्तु ऋण के रूप में उपलब्ध होगा।

योजना में सम्मिलित होने वाले कृषकों को खरीफ 2018 सीजन में नगद ऋण की मात्रा आधे मूलधन राशि से अधिक नहीं होगी। ऋण का शेष भाग वस्तु ऋण के रूप में होगा। किन्तु आगामी रबी सीजन 2018–19 एवं इसके पश्चात आने वाले कृषि मौसमों में यह बंधन लागू नहीं रहेगा और नगद एवं वस्तु ऋण का अनुपात नियमित श्रेणी के कृषकों की भांति रहेगा।

राज्य सहकारी जन-औषधि विपणन संघ का गठन

सभी प्रकार की जन–औषधियाँ एवं ब्रॉण्डेड दवाइयाँ रियायती दरों पर मिलेंगी

भोपाल। सभी प्रकार की जन–औषधियाँ और ब्रॉण्डेड दवाइयों को रियायती दर पर उपलब्ध करवाने के लिये राज्य सहकारी जन–औषधि विपणन संघ का पंजीयन किया गया है। प्रधानमंत्री जन–औषधि परियोजना में देश की जनता को रियायती दरों पर जन–औषधि उपलब्ध कराने की योजना के तहत सहकारिता विभाग द्वारा जन–औषधि संघ का गठन किया गया है।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने बताया कि राज्य सहकारी जन–औषधि विपणन संघ मर्यादित के रूप में संचालित होगा। जन–औषधि केन्द्र के माध्यम से सभी प्रकार की जन–औषधियों और ब्रॉण्डेड दवाइयों को 20 प्रतिशत तक रियायती दरों पर उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया है। सभी जिले एवं विकासखण्ड स्तर पर जन–औषधि केन्द्रों का संचालन किया जायेगा।

श्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में पहली बार सहकारिता के माध्यम से चिकित्सा लाभ के लिये जन–औषधि संघ द्वारा उचित गुणवत्ता की औषधियों के रियायती दर पर विक्रय और भण्डारण की व्यवस्था की जा रही है। जन–औषधि संघ का उद्देश्य सभी प्रकार की औषधियों का न्यूनतम मूल्य पर रोगियों को सीधे लाभ दिलाना तथा इलाज को न्यूनतम मूल्य पर सुनिश्चित कराना होगा। जन–औषधि संघ विश्व–स्तरीय मानक की दवाई कम्पनियों का चयन कर उनकी दवाइयों को रियायती दर पर विक्रय करवाने की व्यवस्था करेगा। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग द्वारा सभी औषधियों के विक्रय का प्रावधान होगा।

श्री सारंग ने बताया कि यह व्यवस्था भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर से प्रारंभ की जा रही है, जो कि बाद में पूरे प्रदेश में की जायेगी। उन्होंने बताया कि संघ द्वारा विभिन्न रोगियों को चिकित्सा जाँच उपलब्ध कराने के लिये आधुनिक पैथालॉजी एवं चिकित्सालय की व्यवस्था की जायेगी। जन–औषधि केन्द्र पैथालॉजी का संचालन कर रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

जन–औषधि संघ द्वारा जन–औषधि की गुणवत्ता, औषधियों का चयन के लिये नियमित परीक्षण कराया जायेगा। संघ द्वारा जन–औषधि केन्द्र, पैथालॉजी एवं चिकित्सालय का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। जन–औषधि केन्द्र के लिये ड्रग लायसेंस मध्यप्रदेश खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा दिया जायेगा। संघ द्वारा प्रत्येक जिले में व्यापार एवं व्यवसाय के रूप में तकनीकी प्रशिक्षुओं को रोजगार के अवसर दिये जायेंगे। चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा जाँच और जन–औषधि रियायती दरों पर उपलब्ध करवाने के लिये विशेष जागरूकता अभियान संचालित होगा। इसका उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व–स्तरीय चिकित्सा सुविधा और गुणवत्ता के साथ औषधियाँ उपलब्ध कराने में प्रदेश को अग्रणी बनाना है।

इन्दौर केन्द्र को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा

डीसीए व पीजीडीसीए पाठ्यक्रम संचालन के लिये संबद्धता प्रदान

इंदौर। म. प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल सहकारिता की शीर्ष संस्था है व म. प्र. शासन का उपक्रम है। उसके द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, किला भवन, किला मैदान, इन्दौर को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा कम्प्यूटर संबंधी एक वर्षीय डीसीए व पीजीडीसीए पाठ्यकम संचालन के लिये संबद्धता प्रदान की गई है। सहकारिता के उद्देश्य अनुसार इन पाठ्यकमों का शुल्क न्यूनतम रखा गया है ताकि हर वर्ग का प्रशिक्षार्थी इन पाठ्यक्रमों में शामिल हो सके। डीसीए का शुल्क मात्र रू. 8,100 व पीजीडीसीए का शुल्क मात्र 9,100 रखा गया है। अत्याधुनिक कम्प्यूटर लेब व योग्य प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिये सत्र समन्वयक श्री शिरीष पुरोहित मोबाईल 99264 51862 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा करवाना ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य

रायसेन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2018 अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित फसलों का बीमा करवाना ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य है एवं अऋणी कृषकों के लिए ऐच्छिक है। कृषकों के लिए प्रीमियम दर मौसम खरीफ में समस्त अनाज तिलहन एवं दलहन फसलों के लिए बीमित राशि का 2.00 प्रतिशत या वास्तविक दर से जो भी कम हो, कपास फसल के लिए बीमित राशि का 5 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो, सभी बीमित अधिसूचित फसल के ऋणि एवं अऋणी कृषकों के लिए क्षतिपूर्ति के लिए 80 प्रतिशत होगा। इस योजना अन्तर्गत बोआई, रोपाई, अंकुरण कम वर्षा एवं प्रतिकूल मौसम दिशाओं के कारण अधिसूचित फसल के अनुकूल 75 प्रतिशत या अधिक क्षतिग्रस्त होने पर जोखिम लागू होगा। फसल कटाई उपरांत अधिकतम 2 सप्ताह के लिए चक्रवात और चक्रवाती वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के मामले में 25 प्रतिशत या अधिक होने पर पूर्ण बीमित इकाई को प्रभावी माना जायेगा।

सौभाग्य योजना से 16 लाख 81 हजार घरों में पहुंची बिजली

19 जिलों में सौ फीसदी विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा

भोपाल। मध्यप्रदेश में सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य" के बेहतर परिणाम अब सामने आने लगे सौभाग्य योजना में अब तक 16 लाख 81 हजार 55 घरों को बिजली कनेक्शन देकर रोशन किया जा चुका है। शेष बचे घरों को आगामी अक्टूबर माह तक विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्यप्रदेश में केन्द्र और राज्य सरकार की प्रभावी पहल पर ऐसे सभी घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो वर्षों से रोशनी से वंचित थे। प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कम्पनी तेजी से प्रयास कर अंधेरे में डूबे सभी घरों को बिजली कनेक्शन सहजता और सरलता से उपलब्ध करवाकर रोशन कर रही हैं।

राज्य के 19 जिलों मंदसौर, नीमच, इंदौर, आगर–मालवा, देवास, खण्डवा, उज्जैन, रतलाम, अशोकनगर, हरदा, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, धार, सिवनी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर एवं झाबुआ में शत–प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर घरों रोशन कर दिया गया हैं। सौभाग्य योजना में 6 जिले अगले कुछ दिनों में शत–प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा करने वाले हैं। इनमें होशंगाबाद 99 प्रतिशत, खरगोन 98 प्रतिशत, ग्वालियर 96 प्रतिशत, अलीराजपुर 96 प्रतिशत, बड़वानी 95 प्रतिशत एवं दतिया 95 प्रतिशत के साथ आगे चल रहे है।

सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन में तीनों विद्युत वितरण कंपनी और उनके क्षेत्रीय और स्थानीय अभियंता और कार्मिक पूरी सक्रियता से कार्य कर रहे हैं, जिससे इस योजना का लाभ हर बिजली विहीन गरीब परिवार तक पहुँच सके। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अब तक 6 लाख 3 हजार 319 घरों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने लक्ष्य के विरूद्ध 6 लाख 84 हजार 633 घरों को रोशन किया है। इसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 3 लाख 93 हजार 103 घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए हैं।

विशेष पिछड़ी जनजाति की महिलाओं के लिये आहार अनुदान योजना

रायसेन। विशेष पिछड़ी जनजाति की महिलाओं के लिये आहार अनुदान योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जायेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिये हितग्राही अपना पंजीयन जनजाति कार्य विभाग में विभागीय ऑनलाईन पोर्टल पर शीघ्र कराएं। जिले के समस्त विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के हितग्राही निकटतम कियोस्क केन्द्र पर जाकर अपना प्रोफाइल पंजीयन करा सकते हैं।

सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हितग्राहियों के प्रोफाइल पंजीयन का कार्य एमपी ऑनलाईन, सीएससी एवं लोक सेवा केन्द्रों पर निरूशुल्क किया जा रहा है। समस्त हितग्राहियों से अपील की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच सचिव, रोजगार सहायक तथा नगरीय क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र के पार्षद से संपर्क कर प्रोफाइल पंजीकरण शीघ्र पूर्ण कराएं, ताकि हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके।

समग्र कृषि पैदावार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मध्यप्रदेश पुरस्कृत

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री सिंह ने नई दिल्ली में दिया पुरस्कार

भोपाल। मध्यप्रदेश को समग्र कृषि पैदावार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये शनिवार को नई दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने यह पुरस्कार इंडिया टुडे पत्रिका के एग्रो समिट एण्ड अवार्ड–2018 समारोह में प्रदान किया। किसान– कल्याण एवं कृषि विभाग के संचालक श्री मोहनलाल ने प्राप्त किया। समग्र कृषि पैदावार में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर, उड़ीसा दूसरे, तेलंगाना तीसरे, आंध्रप्रदेश चौथे और महाराष्ट्र पाँचवें स्थान पर रहा है।

इण्डिया टुडे एग्रो अवार्ड के लिये मध्यप्रदेश को कई कसौटियों पर कसा गया। देश के कृषि विशेषज्ञों ने विभिन्न राज्यों की कृषि सांख्यिकी का अध्ययन किया। इसके बाद यह निष्कर्ष निकला कि मध्यप्रदेश ने वर्ष 2015–16 में गेहूँ की पैदावार बढ़ाने में खास उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में गेहूँ की उत्पादकता 176.80 लाख टन रही है। प्रति हेक्टेयर गेहूँ की उत्पादकता 2,993 किलोग्राम तक पहुँच गई है।

अवार्ड कार्यक्रम में बताया गया कि मध्यप्रदेश देश का वह राज्य है, जिसने खेती में अपना जबरदस्त प्रदर्शन बरकरार रखा है।

राज्य सरकार के कृषि पैदावार के आँकड़े बताते हैं कि खराब दौर में भी मध्यप्रदेश ने कृषि विकास में दोहरे अंकों की वृद्धि दर कायम रखी। समारोह में बताया गया कि केन्द्र सरकार के कृषि और किसान विकास मंत्रालय की ओर से कृषि विकास के लिये दिया जाने वाला कृषि कर्मण अवार्ड पिछले 5 साल से मध्यप्रदेश को मिल रहा है।

समारोह में बताया गया कि कृषि के समग्र विकास के लिये यह जरूरी है कि खेती से जुड़े तमाम पहलुओं पर एक साथ काम किया जाये।

मध्यप्रदेश ने पिछले एक दशक में यही किया है। मध्यप्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाने की सतत कोशिश की गई है। प्रदेश में 700 छोटी सिंचाई परियोजनाओं को वर्ष 2018 के अंत तक पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है। कृषि केबिनेट जैसी व्यवस्था ने भी मध्यप्रदेश को कृषि में अव्वल बनाये रखा है।

उज्जैन व देवास जिले में सायबर सुरक्षा पर कार्यशाला का आयोजन

इंदौर। म. प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल द्वारा सायबर क्राईम व उससे सुरक्षा उपाय तथा कानूनी पहलू पर कार्यशालाओं का आयोजन प्रदेश स्तर पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिनांक 13 जून 2018 को उपायुक्त सहकारिता, उज्जैन कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें संयुक्त आयुक्त श्री बी.एल. मकवाना तथा उपायुक्त श्री ओ.पी. गुप्ता तथा विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। दिनांक 19 जून 2018 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., देवास मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें बैंक के सीईओ डॉ. के. एन. त्रिपाठी, महाप्रबंधक श्री पी. एस. पुरी सहित पेक्स कर्मचारियों ने भाग लिया। दिनांक 20 जून 2018 को उपायुक्त सहकारिता, देवास कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें उपायुक्त डॉ. मनोज जायसवाल, बैंक सीईओ डॉ. के. एन. त्रिपाठी, सहायक आयुक्त कु. वर्षा श्रीवास सहित विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में सायबर अपराध के प्रकार व तरीके के बारे में जानकारी दी गयी तथा इससे सुरक्षा के उपायों के प्रति जागरूक किया गया। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 के प्रावधानो की जानकारी भी प्रदान की गई। सभी ने कार्यकम को वर्तमान समय के अनुसार बहुत उपयोगी बताया। प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यसामग्री भी वितरित की गई। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर के कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्री शिरीष पुरोहित द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

उद्यानिकी फसलों के माध्यम से प्रदेश के किसानों का विकास

भोपाल। प्रदेश को उद्यानिकी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में राज्य सरकार प्रयास कर रही है। विगत 13 वर्षों में उद्यानिकी फसलों जैसे फल–फूल, सब्जी, मसाला, औषधीय पौधों इत्यादि के माध्यम से उद्यानिकी के रकबे में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। उद्यानिकीएवं खाद्य प्र–संस्करण विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषकों को उच्च तकनीक की खेती करने के लिये अनुदान के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है।

शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले को उद्यानिकी के क्षेत्र में विकसित करने के लिये उद्यानिकी एवं खाद्य प्र–संस्करण विभाग द्वारा कृषकों को जागरूक किया गया है। विकासखण्ड कोतमा के ग्राम रेउसा के कृषक श्री धरमदास पिता रामखेलावन के पास कुल एक हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से आधी जमीन पर कृषक द्वारा मिर्च फसल की खेती की गई, जिसमें ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति तथा वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग किया गया। कृषक के अनुसार वह काफी लम्बे समय से मिर्च की खेती करता आ रहा है परंतु पहले केवल लागत के अलावा बहुत कम मुनाफा होता था परंतु उद्यान विभाग के अधिकारियों के सम्पर्क में आने के बाद उसने उन्नत प्रकार के बीज का उपयोग किया तथा ड्रिप सिंचाई एवं वर्मी कम्पोस्ट के माध्यम से प्रति एकड़ लगभग 1.37 लाख रुपये की आय होने लगी है, जो पहले से लगभग दोगुनी है। इससे प्रोत्साहित होकर कृषक उद्यानिकी के रकबे में वृद्धि करने की तैयारी कर रहा है। इसी प्रकार विकासखण्ड कोतमा के ग्राम बसखला के कृषक समयलाल पिता पूरन, जो पूर्व वर्षों में उद्यानिकी की खेती परम्परागत तरीके से करता था, उद्यान विभाग में अधिकारियों के सम्पर्क में आने के बाद विभाग में पंजीयन करवाया, जिससे उसे ड्रिप एवं मल्चिंग योजना का लाभ लेकर आधुनिक पद्धति से खेती करना शुरू किया तथा टमाटर के हाइब्रिड बीज एवं वर्मी कम्पोस्ट खाद का उपयोग कर 0.100 हेक्टेयर में टमाटर की खेती की, जिससे उसे लगभग 3 टन का उत्पादन प्राप्त हुआ, जिसे कृषक ने स्थानीय बाजार में बेचकर 60 हजार रुपये का मुनाफा कमाया है।

इस प्रकार राज्य सरकार की मंशानुसार उद्यानिकीएवं खाद्य प्र–संस्करण विभाग के सतत प्रयास एवं कृषकों से जीवंत सम्पर्क बनाकर विभागीय योजनाओं के माध्यम से कृषकों की आय दोगुनी करने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।

समाज में झूठ, भ्रम, निराशा फैलाने वालों की कोई जगह नहीं - प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री द्वारा राजगढ़ में लगभग 4000 करोड़ की मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का लोकार्पण

भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजगढ़ जिले में लगभग 4000 करोड़ रुपये लागत की मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करते हुए डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी को 65वीं पुण्य–तिथि पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार डॉ. मुखर्जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए देशवासियों के सपनों को पूरा करेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, भारत सरकार की प्राथमिकता होगी ताकि युवाओं को अच्छी उच्च शिक्षा मिले और वे समाज की सेवा करने के लिये हमेशा समर्पित रह सकें। उन्होंने कहा कि विद्या, वित्त और विकास का आपस में समन्वय होना चाहिये, शैक्षणिक संस्थाओं और औद्योगिक संगठनों की सोच में एकरूपता होनी चाहिये, तभी भारत देश आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। श्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने देश के निर्माण और विकास में डॉ. मुखर्जी जैसी अनेक महान हस्तियों के योगदान को भुला दिया था। इस कमी को हमारी सरकार पूरा कर रही है। हम देश के महान व्यक्तित्वों और सपूतों के सपनों को पूरा करेंगे। शासन का पहला काम जनसेवा और लोगों का जीवन–स्तर ऊँचा उठाना है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों के सपनों को पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम पूर्ववर्ती सरकारों की कमियों को नहीं दोहरायेंगे। लोगों की क्षमताओं और संसाधनों की अनदेखी नहीं की जायेगी। लोकार्पण समारोह में किसानों और ग्रामीणों के जन–सैलाब को देखते हुए श्री मोदी ने कहा कि अब समाज में झूठ फैलाने वालों, भ्रम फैलाने वालों और निराशा फैलाने वालों की कोई जगह नहीं है। देशवासियों ने हमारी नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है। हम इस विश्वास को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे।

माइक्रो एरीगेशन को बढ़ावा देगी भारत सरकार

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सिंचाई परियोजनाओं के पानी की एक–एक बूँद का सिंचाई में भरपूर उपयोग सुनिश्चित करने के लिये देश में माइक्रो एरीगेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में माइक्रो एरीगेशन सिस्टम से सिंचाई सुविधा दी जा रही है। इसमें से साढ़े 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र मध्यप्रदेश का है। हाल ही में किसानों से हुई चर्चा का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में आदिवासी अंचल की महिला कृषकों ने ड्रिप एरीगेशन सिस्टम से टमाटर की उन्नत खेती कर रिकार्ड कायम किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ अभी 35 लाख किसानों को मिल रहा है। देश में 575 से अधिक कृषि उपज मण्डियों का इंटीग्रेटेड नेटवर्क बना लिया गया है, जिसमें मध्यप्रदेश की 58 मण्डियाँ नेटवर्क के माध्यम से जुड़ गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सिस्टम से किसान अपनी उपज सीधे मण्डी में बेच सकेगा। उन्होंने जानकारी दी कि मुद्रा बैंक योजना में बैंक गारंटी के साथ लोगों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस योजना में मध्यप्रदेश के 45 लाख किसानों को फायदा मिला है।

प्रधानमंत्री ने मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना की परिकल्पना से निर्माण होने तक इससे जुड़े हर व्यक्ति का अभिनंदन करते हुए कहा कि यह परियोजना केवल राजगढ़ की नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश की ऐसी बड़ी परियोजनाओं में से एक है, जिससे 725 गाँव को सीधा लाभ मिलेगा। इन गाँवों में पीने के पानी की भरपूर व्यवस्था सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को पूरा कर वास्तव में मध्यप्रदेश में माताओं–बहनों और किसानों की बेहतरी के लिये काम किया है। इस परियोजना से प्रदेश के मालवा अंचल की समृद्धि का सशक्त मार्ग प्रशस्त होगा।

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि श्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य को पिछड़ेपन की पहचान से मुक्त करवा दिया है। राजगढ़ जिले में इस वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण मुख्यमंत्री की सोच और दूरदृष्टि का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के समग्र विकास के साथ–साथ विश्व में शांति की स्थापना के लिये महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। श्री मोदी अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन गये हैं। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की यह पहली ऐतिहासिक राजगढ़ यात्रा है। उन्होंने बताया कि श्री मोदी प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली योजनाएँ लेकर आये हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना राजगढ़ जिले की तस्वीर बदल देगी। उन्होंने बताया कि खेती और सिंचाई के क्षेत्र में मध्यप्रदेश के किसानों ने पंजाब राज्य को भी पीछे छोड़ दिया है। मध्यप्रदेश में पिछले कई वर्षों से कृषि के क्षेत्र में रिकार्ड उत्पादन हो रहा है। राज्य सरकार की योजना है कि आने वाले कुछ वर्षों में प्रदेश में सिंचाई क्षमता को 80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक बढ़ाया जायेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के मिशन को पूरा करने में मध्यप्रदेश राज्य पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। श्री चौहान ने बताया कि पिछली सरकारों में प्रदेश के किसानों को बिजली, पानी, सड़क और खाद को लेकर हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं है। प्रदेश के किसानों को यह सभी सुविधाएँ आसानी से उनके गाँवों और खेतों तक मिल रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राजगढ़वासियों का आव्हान किया कि नया मध्यप्रदेश बनाने के साथ–साथ नया राजगढ़ बनाने में भी अपना भरपूर सहयोग प्रदान करें, संकल्पित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में हुई तरक्की और लोगों की खुशहाली की चर्चा करते हुए कहा कि यह प्रदेश, देश के विकासशील प्रदेशों में शामिल हो गया है। प्रदेश ने पिछड़ेपन की पहचान को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजगढ़ जिला एस्पिरेशन जिला बन गया है। अब यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ग्राम विकास अभियान में मध्यप्रदेश के एक्पिरेशन जिलों में विभिन्न विकास गतिविधियाँ लागू की जायेंगी। इन जिलों के हर गाँव के हर घर में घरेलू गैस कनेक्शन होंगे। हर परिवार का बैंक खाता होगा। हर गाँव का सम्पूर्ण टीकाकरण होगा। हर गाँव में सभी बुनियादी सुविधाएँ होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के सपनों का भारत, गाँवों की तरक्की से ही निर्मित होगा।

लोकार्पण समारोह के प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को तुलसी की माला भेंट की और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सिंचाई कार्य–योजना का विमोचन किया। समारोह में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, सांसद श्री राकेश सिंह, श्री रोडमल नागर, स्थानीय विधायकगण, अन्य जन–प्रतिनिधि, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री आर. के. शुक्ला और जन– सैलाब के रूप में नागरिक और किसान मौजूद थे।

महिला एवं बाल विकास कार्यालय का नाम परिवर्तित

अशोकनगर। प्रदेश सरकार ने एकीकृत बाल विकास सेवा तथा महिला सशक्तिकरण विभागों को मिलाकर पुनः महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया है। इसलिए अब जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा तथा जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी दोनों के कार्यालय का नाम जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास होगा।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से सहकारिता के आधार को मजबूती मिलेगी

इंदौर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आरपीएल प्रशिक्षण प्राप्त उतीर्ण सहकारी संस्था के 382 कर्मचारियों को प्रमाण पत्र वितरित

इंदौर। म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आरपीएल प्रशिक्षण प्राप्त उतीर्ण सहकारी संस्था के 382 कर्मचारियों को मुख्य अतिथि श्री भंवरसिंह शेखावत विधायक बदनावर, इंदौर प्रीमियर को–आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री उमानारायण सिंह पटेल की अध्यक्षता एवं उपायुक्त सहकारिता श्री के. पाटनकर, सहकारी शिक्षाविद डा. डी.पी. गर्ग एवं सहकारी प्रबंध संस्थान के पूर्व प्राचार्य श्री वाय.एस. पवार के विशेष आतिथ्य में प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम समारोह पूर्वक सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में रतलाम, झाबुआ, इंदौर, उज्जैन, खण्डवा व धार जिले की सहकारी संस्था के 400 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुवे मुख्य अतिथि श्री भंवरसिंह शेखावत ने कहा की सहकारिता के बगैर समाज व देश नहीं चल सकता। सहकारी संस्था की समृद्धि व सक्षमता के लिए नेतृत्व व प्रबंधन को ''नवाचार'' की रूपरेखा पर सोचना होगा।

अध्यक्षता करते हुये श्री उमानारायण पटेल ने कहा की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सहकारिता के आधार को मजबूती प्रदान करेगा। हम इसके माध्यम से नये विकास कार्यक्रम को योजनाबद्ध तरीके से लागू कर समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। उपायुक्त सहकारिता श्री के. पाटनकर ने बताया की वर्तमान में सहकारी संस्थायें वर्तमान में के.सी.सी. व उपभोक्ता भण्डार संचालन व शासन की योजनाओं से सम्बन्धित काम कर रही है। लेकिन संस्था के जरिये हमें सदस्यों व समाज की अन्य

आवश्यकताओं के लिये कार्यक्रम बनाना होगा। सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण प्रभारी श्री के.एल. राठौर ने स्वागत भाषण में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षण की विस्तृत जानकारी दी।

प्रारंभ में माँ सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण व दीपप्रज्वलन कर अतिथियों द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अतिथियों का पुष्प मालाओं से अभिनन्दन केन्द्र के प्राचार्य श्री निरंजन कुमार कसारा, राज्य समन्वयक श्री संतोष येड़े व व्याख्याता गणेश प्रसाद मांझी, दिलीप मरमट, कम्प्यूटर प्रशिक्षक शिरीष पुरोहित, कालका श्रीवास्तव, जिला सहकारी संघ के प्रबंधक श्री दौलत राठौर, सहकारी निरीक्षक श्री अरूण पाण्डेय व श्री अखिलेश नेमा ने किया। कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य श्री निरंजन कुमार कसारा ने किया व आभार व्याख्याता श्री गणेशप्रसाद मांझी ने व्यक्त किया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।